RAJYA SABHA

Friday, the 18th December, 1998/27 Agrahayana, 1920 (Saka)

The House met at eleven ot the clock.
Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shifting of Regional Meteorological Centre

*281. SHRI VIJAY J. DARDA:
SHRI RAGHAVJI: †

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in "Lok Mat Times", Nagpur dated 2nd November, 1998 under the caption "Met Office transfer move to be dealt with tooth and nail."

(b) if so, the reaction of government to the observations made therein and facts of the matter, alongwith justification for the move to shift Regional Meteorological office from Nagpur to Bhopal or Jabalpur.

(c) the details of representations received in this regard and the action taken thereon; and

(d) the present status of the proposal?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ): सरकार को, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र नागपुर को भोपाल/जबलपुर में स्थानान्तरित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार, संसद सदस्य और मध्य प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्टाफ एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव के विरुद्ध भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार का यह दृष्टिकोण है कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के कार्यालय को नागपुर से स्थानान्तरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राघवजी: सभापति जी, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह जानकारी अवश्य होगी कि मध्य प्रदेश—पूरे प्रदेश—में मौसम विज्ञान का कोई कार्यालय नहीं है जबकि महाराष्ट्र में मौसम विभाग के सात कार्यालय हैं—पूना में 5, मुम्बई में 1 और नागपुर में 1, जबकि मध्य प्रदेश में शून्य बावजूद इसके कि मध्य प्रदेश के 62 जिले नागपुर कार्यालय से गवर्न होते हैं जबकि महाराष्ट्र के केवल 9 विदर्भ के जिले। इसी प्रकार से भूकंप का प्रकोप मध्य प्रदेश में प्रायः देखने को मिलता है। खंडवा, जबलपुर और अन्य स्थानों पर झटके लग चुके हैं। मध्य प्रदेश के 16 शाखा कार्यालय नागपुर के कार्यालय से संचालित होते हैं जबकि महाराष्ट्र के केवल 2 शाखा कार्यालय नागपुर से संचालित होते हैं—अकोला और नागपुर। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय शोध प्रयोगशाला और अखिल भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इनके लिए भी मौसम विज्ञान के कार्यालय की सहायता बहुत जरूरी है। इसके अलावा 4 मेजर एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में है—भोपाल, रायपुर, इन्दौर और खजुराहो। ऐसी सारी स्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है—

"Government are of the view that there is no need to shift the office of the Regional Meteorological Centre from Nagpur."

तो मुझे आश्चर्य होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और प्रश्न करता हूं कि क्या वे इस पर पुनर्विचार करके नागपुर का कार्यालय भोपाल में स्थानांतरित करने पर विचार करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदय, पांच एयर कमांड्स इस देश में है और उनसे संबंधित पांच ऐसे मौसम विज्ञान के कार्यालय हैं और काम करते हैं—वायु सेना और वायु आवागमन की दृष्टि से। ये 1945 से काम कर रहे हैं—एक मुम्बई में, एक चेन्नई में, एक नागपुर में, एक कलकत्ता में और एक दिल्ली में। ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान कार्यालय कहलाते हैं। इसके बाद 1996 में कुछ विशेष कारणों से पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में भी एक कार्यालय स्थापित किया गया। लेकिन क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए 1972 और 1976 के बीच में प्रत्येक महत्वपूर्ण राज्य—जो बड़े राज्य हैं—की राजधानी में एक-एक कार्यालय खोला गया। यह मैटियारालाजिकल सेंटर, मौसम विज्ञान का केन्द्र कहलाते हैं। भोपाल में 1976 में स्थापित हुआ। इसमें तथा नागपुर के कार्यालय में जहां तक इनके इक्विपमेंट्स का सवाल है कोई अंतर नहीं है। काम करने की शैली का

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raghavji.

कोई अंतर नहीं है। आप देखें कि आर०एम०सी० नागपुर में 1998 में 64 अधिकारी हैं और भोपाल में 52 अधिकारी। पायलट बैलून आब्जरवेट्री 6 नागपुर में हैं, 5 भोपाल में। अपर एयर आब्जरवेट्री 5 नागपुर में हैं, 4 भोपाल में। सिस्मालोजिकल लेबोरेटरी नागपुर में 4 हैं और भोपाल में दो हैं, एग्रो मैटेरियोलाजिकल सेंटर्स नागपुर में 6 हैं और भोपाल में 4 हैं, रेनगॉज क्षेत्रीय स्टेशंस 259 नागपुर कवर करता है और 171 भोपाल कवर करता है। इसी तरह से नान-डिपार्टमेंटल स्टेट रेन गेज 636 नागपुर में और 434 भोपाल में हैं। तो आप देखेंगे कि अंतर इतना ही है कि नागपुर का कार्यालय 24 घंटे काम करता है और भोपाल का 18 घंटे काम करता है, लेकिन अगर भोपाल वाला कार्यालय के भी 24 घंटे काम करने की जरूरत हो तो वह भी करने की इजाजत दी जा सकती है। महोदय, नागपुर का कार्यालय वायुसेना और विमान के आवागमन की दृष्टि से बहुत पहले से काम करता आ रहा है। उस का एक विशेष महत्व है। इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखते हुए नागपुर केन्द्र को हटाने की कोई आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करती।

श्री राघवजी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह इम्प्रेशन कराने की बहुत कोशिश की है कि भोपाल के कार्यालय और नागपुर के कार्यालय में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन सब से बड़ा अंतर यह तो है ही कि भोपाल का कार्यालय नागपुर के कार्यालय का शाखा कार्यालय ही है, मुख्य कार्यालय नहीं है जबकि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी मुख्य कार्यालय नहीं है। क्या ऐसा कोई मनुस्मृति का या और कोई ऐसा नियम बन गया है कि पांचवें से छठा कार्यालय खुलेगा ही नहीं। महोदय, नागपुर में कार्यालय बना रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप विदर्भ नागपुर से गवर्न करवाइए, लेकिन पांचवें से छठा कार्यालय खोलने और भोपाल वाले कार्यालय को मुख्यालय घोषित करने में आप को क्या आपत्ति है? सारी व्यवस्थाएं वहां मौजूद हैं और आप को अतिरिक्त ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसा कोई ठोस नियम मत बनाइए कि पांचवें से छठा कार्यालय हिंदुस्तान में खुलेगा ही नहीं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे भोपाल में छठा कार्यालय खोले जाने की घोषणा करने की कृपा करें।

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raghavji.

डा० मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन् जैसा कि मैंने बताया नागपुर का जो कार्यालय है, वह क्षेत्रीय कार्यालय है। देश में ऐसे 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भोपाल तथा अन्य बड़े राज्यों की राजधानियों में राज्यों के केन्द्र हैं। भोपल एक महत्वपूर्ण केन्द्र है और उस के विकास के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा और वायुयान आवागमन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए नागपुर कार्यालय काम करता है। वह क्षेत्रीय कार्यालय है और जितना क्षेत्र होता है उस में दो-चार प्रांत आते हैं। अब इस को यह न समझा जाये कि यह विदर्भ के लिए है। महोदय, उन को शायद गलतफहमी यह है कि नागपुर कार्यालय विदर्भ के लिए है, ऐसा नहीं है। अलग-अलग कार्यालयों की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं, उन की विशेषताएं हैं और उस के अनुसार वह काम करते हैं। सरकार का ऐसा निर्णय नहीं है कि आगे छठा या सातवां नहीं खुलेगा। फिलहाल निर्णय इतना ही है कि नागपुर के कार्यालय को भोपाल नहीं लाना है।

SHRI O. RAJAGOPAL: Mr. Chairman, Sir, so far as the Regional Meteorological office at Nagpur is concerned, we have no complaint. But the point is, Madhya Pradesh being the biggest State in the country, and in view of its diverse climatic conditions, and another State, Chhatisgarh is going to be created out of Madhya Pradesh, I would like to know from the hon. Minister whether he will review the existing position and have another regional office in this area. When Chhatisgarh State is created from Madhya Pradesh, it is supposed to have its capital in Raipur. There is a need for taking into account the extensive nature of the State. I would like to know whether the Minister will reconsider the existing position.

डा० मुरली मनोहर जोशी: यह स्टेट के क्षेत्रफल या स्टेट के आकार-प्रकार पर निर्भर नहीं करते। यह तो मौसम विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से और आवागमन तथा सुरक्षा की दृष्टि से कि कहां आवश्यकता है, उस पर निर्भर करते हैं। जैसे हम ने गोहाटी में एक नया कार्यालय पिछले दिनों खोला। सुरक्षा और आवागमन की दृष्टि से आवश्यकता पड़ी तो खोल दिया। यहां भी आप देखें, मैं ने पहले भी बताया कि कोई फर्क नहीं है इन दोनों में आर०एम०सी० नागपुर सेटेलाइट रिसीविंग

इक्युपमेंट है, यहां भी है, नेशनल हायड्रोलॉजिकल सेंटर नागपुर में भी है, यहां भी है, वी०पी० सेट यहां भी है, वहां भी है, सिस्मालौजिकल आब्जर्वेटरी नागपुर में नहीं है, भोपाल में है, इलेक्ट्रानिक टेलिप्रिंटर मशीन दोनों जगह है, पर्सनल कम्प्यूटर दोनों जगह है, नई बिल्डिंग भोपाल में बनी है, नागपुर में पहले से है, एअरपोर्ट मैटेरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम नागपुर में है, भोपाल में नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां भी डाला जा सकता है। इस तरह सारी सुविधाएं बराबर है। केवल नाम के लिए यह कहना कि उस का नाम अब क्षेत्रीय कर दिया जाए, मैं नहीं समझता कि उस की आवश्यकता है क्योंकि हमारी जो अन्य आवश्यकताएं हैं, उस को देखते हुए यह किया गया है।

श्री लक्खीराम अग्रवाल: सभापति महोदय, वैसे तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पांचवें कार्यालय के बाद छठवां कार्यालय गुवाहटी में खोलने का निर्णय किया है, उसी प्रकार भले ही यह नागपुर का कार्यालय स्थानान्तरित न किया जाए, लेकिन भोपाल में भी वहां इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, अभी तक जो जांच कराई जा चुकी है, उसके अनुसार आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पांच से छह या छह से सात नहीं होंगे। यह तो आवश्यकता के अनुसार, मौसम विभाग की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार, वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार, आवागमन की आवश्यकता के अनुसार, जैसी भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी, वैसा सरकार निर्णय करेगी।

Medical Colleges in Assam

*282. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned any money to Assam Government for improving the medical colleges at Dibrugarh, Guwahati and Silchar, during the last three years;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (c) The Planning Commission has provided Central Assistance of Rs. 2 crores for improvement of emergency care services in Guwahati Medical College, Assam in Annual Plan 1996-97. In addition, funds are provided on yearly basis by the Planning Commission for support to the Guwahati Medical College, Assam and through the North Eastern Council under its scheme to support medical colleges *viz.* Assam Medical College, Guwahati Medical College and Silchar Medical College.

The North Eastern Council Secretariat has further informed that through an ongoing scheme for supporting development of three medical colleges in Assam since 1996-97, funds to the tune of Rs. 336.86 lakhs have been released. Under this scheme, it is proposed to cover all the medical colleges in Assam during the entire 9th Five-year Plan for which a provision of Rs. 40.00 crores has been made. By another scheme for providing support for the development of Guwahati Medical College, an amount of Rs. 103.00 lakhs has been released during the 8th Five Year Plan and Rs. 50.00 lakhs during 1997-98. The provision under this scheme for 9th Five Year Plan is Rs. 2.00 crores. Further, under a scheme for construction of Paying Cabins, an amount of Rs. 10.00 lakhs in 1997-98 has been released for construction of paying cabins in the three medical colleges of Assam at Dibrugarh, Guwahati and Silchar.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Mr. Chairman, Sir, my first supplementary is this. The three medical colleges at Dibrugarh, Guwahati and Silchar were established to cater to the needs of health-care of not only Assam but also of the other States of north-eastern region.